Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 2285–2289

STUDY OF MULTIPLE ENTRY OF ADOLESCENT STUDENTS STUDYING IN UNDERGRADUATE COLLEGES: IN THE CONTEXT OF NATIONAL EDUCATION POLICY 2020

स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि का अध्ययन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में

Devki Rawat [1], Bindu Singh [2]

[1] Research Scholar, Department of Pedagogy, IFTM University Moradabad, India
[2] Assistant Professor, Department of Pedagogy, IFTM University Moradabad, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.5333

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: The National Education Policy 2020 is a revolutionary step towards bringing about a comprehensive reform in the educational structure of India. This policy emphasizes on making higher education more flexible and inclusive by implementing multiple-entry and multiple-exit system. In the context of this policy, it is very important to study multiple entry of adolescent students studying in undergraduate colleges, as it not only makes their educational journey more convenient but also empowers their skill development and career building. The multiple entry system allows students to continue their education or stop at a specific stage according to their personal, economic, and social needs. Under this system, students can complete their undergraduate education at different levels within one to four years. For example, there is a provision to get a certificate after completing one year of study, a diploma after two years, a bachelor's degree after three years, and a bachelor's degree with research work in four years. This will benefit students who are forced to leave their studies for some reason, as they can resume their studies from the same level where they left. This system can prove to be extremely beneficial for adolescent students in colleges, as many students of this age group are unable to continue their studies due to financial difficulties, personal responsibilities, or other reasons. The multiple entry system provides them an opportunity to re-engage in education, so that they can achieve their goals without any educational disruption. This flexibility also allows students to balance their education with various skill courses and employment opportunities. The concept of academic credit bank has also been introduced to make the multiple entry system effective under the National Education Policy 2020. It is a digital database in which the credits earned by the students are stored and they can resume their education by using them when needed. This initiative provides flexibility and diversity to the students in different subjects, so that they can choose courses according to their interest and career requirements. It is clear from this study that the multiple-entry system not only provides a golden opportunity to adolescent students to complete their education, but also helps them to become self-reliant. This policy eliminates the rigidity of the traditional education system and makes it more inclusive and flexible, so that students can get education according to their ability. Findings obtained from the research study - No significant difference was found on the basis of gender in the multiple entry of adolescent students studying in graduate level colleges of Bijnor district, No significant difference was found on the basis of regional in the multiple entry of adolescent students studying in graduate level colleges of Bijnor district.

Hindi: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शैक्षिक ढांचे में व्यापक सुधार लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह नीति बहु-प्रविष्टि और बहु-निकास प्रणाली को लागू करके उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और

समावेशी बनाने पर बल देती है। इस नीति के संदर्भ में, स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत किशोरवय विद्यार्थियों की बहु-प्रविष्टि का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनके शैक्षिक सफर को अधिक अनुकूल बनाता है, बल्कि उनके कौशल विकास और करियर निर्माण को भी सशक्त करता है। बहु-प्रविष्टि प्रणाली विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत, आर्थिक, और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शिक्षा को जारी रखने या किसी विशिष्ट चरण पर रोकने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली के तहत, विद्यार्थी अपनी स्नातक शिक्षा को एक से चार वर्षों के भीतर विभिन्न स्तरों पर पूर्ण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्षों के पश्चात डिप्लोमा, तीन वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री, और चार वर्षों में शोध कार्य सहित स्नातक की उपाधि प्राप्त करने का प्रावधान है। इससे उन विद्यार्थियों को लाभ होगा जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई को पुनः उसी स्तर से आरंभ कर सकते हैं जहाँ उन्होंने छोड़ा था। महाविद्यालयों में किशोरवय विद्यार्थियों के लिए यह प्रणाली अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस आयु वर्ग के कई छात्र आर्थिक कठिनाइयों, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों, या अन्य कारणों से अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। बहु-प्रविष्टि प्रणाली उन्हें शिक्षा के प्रति पुनः जुड़ाव का अवसर प्रदान करती है, जिससे वे बिना किसी शैक्षिक व्यवधान के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह लचीलापन विद्यार्थियों को विभिन्न कौशल पाठ्यक्रमों और रोजगार के अवसरों के साथ अपनी शिक्षा को संतुलित करने की सुविधा भी देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहु-प्रविष्टि प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की अवधारणा को भी लागू किया गया है। यह एक डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें विद्यार्थियों के अर्जित किए गए क्रेडिट संग्रहीत किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करके वे अपनी शिक्षा को पुनः आरंभ कर सकते हैं। यह पहल छात्रों को विभिन्न विषयों में लचीलापन और विविधता प्रदान करती है, जिससे वे अपने रुचि और करियर की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बहु-प्रविष्टि प्रणाली न केवल किशोरवय विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करती है। यह नीति पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की कठोरता को समाप्त करके उसे अधिक समावेशी और लचीला बनाती है, जिससे विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष - बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि में लैगिंक आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया, बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थीयों की बहु प्रविष्टि में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

Keywords: Graduate Level Students, Multiple Entry, Adolescent Students स्नताक स्तर के विद्यार्थी, बहु प्रविष्टि, किशोरवय विद्यार्थी

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और कौशल-आधारित बनाना है। यह नीति विशेष रूप से स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं, परिस्थितियों और रुचियों के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। बहु प्रविष्टि और निर्गम प्रणाली उच्च शिक्षा में नवाचार और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रणाली के तहत विद्यार्थी किसी भी समय अपने अध्ययन को रोक सकते हैं और उपयुक्त प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे बाद में पुनः अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। यह विशेष रूप से उन किशोरवय विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा को निर्बाध रूप से पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी एक, दो या तीन वर्षों की अवधि के बाद क्रमशः प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने करियर को लचीले ढंग से प्रबंधित करने का अवसर प्राप्त होता है। भारत में किशोरवय विद्यार्थी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं, जिनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र, तथा वे छात्र शामिल हैं जो शिक्षा के साथ-साथ रोजगार या अन्य पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में, MEES प्रणाली इन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जिससे वे बिना शिक्षा बाधित किए अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से लड़कियों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें शिक्षा छोड़ने के दबाव से मुक्त करती है और उनके पुनः शिक्षा प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहु प्रविष्टि और निर्गम प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर को 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है। यह नीति विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में MEES को लागू करने से न केवल विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में भी सुधार होगा।

शोधकर्ताओं का मानना है कि MEES प्रणाली विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ कर सकती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में, यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ देता है, तो उसे पुनः उसी स्तर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, जिससे वे अक्सर निराश हो जाते हैं और शिक्षा से दूर हो जाते हैं। MEES प्रणाली इस समस्या का समाधान प्रदान करती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा को चरणबद्ध रूप से पूरा करने की अनुमति देती है। इस प्रणाली में अकादमिक क्रेडिट बैंक की अवधारणा भी शामिल की गई है, जिससे विद्यार्थी अपने अर्जित क्रेडिट को संग्रहीत कर सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग करके अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं।

भारत में MEES की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संरचनात्मक तैयारियाँ, तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों की जागरूकता शामिल हैं। इस प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन के लिए महाविद्यालयों को अपनी पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने होंगे। इसके अलावा, शिक्षकों को भी इस प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। विद्यार्थियों की जागरूकता भी इस प्रणाली की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि जब तक विद्यार्थी इस प्रणाली के लाभों को नहीं समझेंगे, तब तक वे इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे।

हालांकि, MEES प्रणाली को अपनाने में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विद्यार्थी इस प्रणाली को अपनाने में झिझक सकते हैं, क्योंकि वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से परिचित हैं और नए ढांचे को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा, महाविद्यालयों को अपनी प्रशासनिक और तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता होगी, ताकि वे इस प्रणाली को सुचारु रूप से लागू कर सकें। वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति योजनाओं को भी इस प्रणाली के साथ जोड़ने की आवश्यकता होगी, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी भी इसका पूरा लाभ उठा सकें।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि MEES प्रणाली स्नातक स्तर पर अध्ययनरत किशोरवय विद्यार्थियों के लिए कितनी प्रभावी और उपयोगी है। यह अध्ययन न केवल नीति-निर्माताओं और शिक्षाविदों को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, बल्कि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी इस प्रणाली के लाभों और चुनौतियों को स्पष्ट करेगा। इस संदर्भ में, यह शोध शिक्षा प्रणाली में सुधार और विद्यार्थियों की शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित बहु प्रविष्टि और निर्गम प्रणाली स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकती है, जिससे वे अपनी शिक्षा को अधिक प्रभावी, लचीला और उपयोगी बना सकें। यदि इस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो यह भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने में सहायक होगी।

2. आवश्यकता एवं महत्व

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने हेतु एक क्रांतिकारी पहल है। यह नीति विशेष रूप से उच्च शिक्षा में लचीलापन, समावेशन और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने पर बल देती है। इस संदर्भ में स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में उभरकर सामने आई है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक यात्रा में अधिक स्वतंत्रता और विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और समावेशी बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कठोर थी, जिसमें एक बार प्रवेश लेने के बाद यदि किसी कारणवश विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाता था, तो उसे शिक्षा छोड़नी पड़ती थी। इस स्थिति में उसे न तो कोई प्रमाणपत्र मिलता था और न ही वह अपने पहले के अध्ययन का कोई लाभ उठा पाता था। इसके अलावा, विद्यार्थी को यदि कुछ वर्षों के अंतराल के बाद पुनः शिक्षा शुरू करनी हो, तो उसे प्रारंभ से ही अध्ययन करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए बहु प्रविष्टि प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जो छात्रों को अपनी शिक्षा को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधित करने का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त, भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत या अन्य कारणों से कई छात्र अपनी शिक्षा बीच में छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में यदि एक लचीली शिक्षा प्रणाली उपलब्ध हो, तो यह न केवल शिक्षा दर को बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लाभों से जोड़ने का कार्य भी करेगी। बहु प्रविष्टि प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह प्रणाली न केवल उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाती है, बल्कि छात्रों को अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद भी करती है। छम्च् 2020 द्वारा प्रस्तावित इस प्रणाली से भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और व्यावहारिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक ऐसा कदम है, जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।

3. सम्बन्धित शोध साहित्य अध्ययन

रीना मोदी (2015), सूर्यकान्त रतन चौगुले (2015), सरलेश, मौर्य (2017), मिनी अग्रवाल, के.एस. ठाकुर (2019), सुहागिन स्निग्धा (2020) आदि प्रमुख है।

4. समस्या कथन

स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि का अध्ययन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में।

5. शोध अध्ययन के उद्देश्य

1) बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि का लैगिंक आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।
2) बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि का क्षेत्रीय आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।

5.1. शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

1) बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि में लैगिंक आधार पर सार्थक अन्तर नहीं हैं।
2) बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं हैं।

5.2. आंकड़ा संग्रहण के उपकरण

प्रस्तुत शोध हेतु आंकड़ों के संकलन के लिए बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया।

न्यादर्श

वर्तमान शोध हेतु 600 किशोरवय विद्यार्थी को शामिल किया गया है।

उपकरण

बहु प्रविष्टि मापने हेतु - स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

6. परिकल्पनाओं का परिभाषीकरण

तालिका संख्या - 1

बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय छात्र एवं छात्राओं की बहु प्रविष्टि का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात का विश्लेषण एवं व्याख्या

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
छात्र	320	88.79	20.33	1.79	सार्थक नहीं
छात्राऐं	280	86.86	16.96		

व्याख्या

बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय छात्र एवं छात्राओं की बहु प्रविष्टि को दर्शाया गया है। तालिका में बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय छात्रों की बहु प्रविष्टि का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 88.79 एवं 20.22 प्राप्त हुआ है लेकिन बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय छात्राओं की बहु प्रविष्टि का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 86.86 एवं 16.96 प्राप्त हुआ जो दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात का मान 1.79 प्राप्त हुआ। जिससे पता चलता है कि बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय छात्र एवं छात्राओं की बहु प्रविष्टि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या - 2

बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि का मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात का विश्लेषण एवं व्याख्या

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
शहरी विद्यार्थी	304	88.09	20.03	0.66	सार्थक नहीं
ग्रामीण विद्यार्थी	296	87.96	19.07		

व्याख्या

बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि को दर्शाया गया है। तालिका में बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय शहरी विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 88.09 एवं 20.03 प्राप्त हुआ है लेकिन बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय ग्रामीण विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 87.96 एवं 19.07 प्राप्त हुआ जो दोनों समूहों के मध्य क्रान्तिक अनुपात का मान 0.66 प्राप्त हुआ। जिससे पता चलता है कि बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

7. निष्कर्ष

1) बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि में लैगिंक आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
2) बिजनौर जनपद के स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् किशोरवय विद्यार्थियों की बहु प्रविष्टि में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

शिक्षा मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार (बेसिक शिक्षा) शिक्षा सत्र (2000-2001). नैतिक शिक्षा 1 से 5 तक।
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार (1990) भारतीय परिदृश्य में 2000 तक सबको शिक्षा, नई दिल्ली।
काशीनाथ, एच०एम० (1980) एक्रिटिकल सर्वे आफ दा प्राबलम आफ बेस्टेज,
एण्ड सओनीशन इन प्राइमरी एजूकेशन इन कर्नाटक स्टेट इन एम०बी० बुचार्ड सर्वे रिर्पोट 1978-83 एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली।
गेरेट, हेनरी ई० (1979) स्टेटिस्टक इन साइकोलाजी एण्ड एजूकेशन विकास एफ०एण्ड एस०लि० बाम्बे।
बुच, एम०बी० (1991) फोर्थ सर्वे रिसर्च इन एजूकेशन 1983-88 एन० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली।
अग्रवाल एस०के०, मेरठ मॉडर्न पब्लिसर्सः शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्त, 1985